संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 16

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क. वस्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए) **बजट 2004-2005** संशोधित 2004-2005 बजट 2005-2006 मुख्य शीर्ष आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़ आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़ आयोजना आयोजना-भिन्न जोड़ राजस्व 700.50 36.00 736.50 600.50 35.00 635.50 838.30 36.00 874.30 पूंजी 49.50 49.50 49.50 49.50 91.00 91.00 जोड़ 750.00 36.00 786.00 650.00 35.00 685.00 929.30 36.00 965.30 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 1. 3451 10.50 19.00 29.50 10.50 18.00 28.50 9.70 19.00 28.70 दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग राष्ट्रीय सूचना केन्द्र 3451 157.60 157.60 157.60 172.00 172.00 157.60 5475 34.40 34.40 34.40 34.40 62.00 62.00 जोड़ 192.00 192.00 192.00 192.00 234.00 234.00 प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं 2852 17.00 5.00 5.00 5.00 5.00 17.00 रोबोटिक्स सहित औद्योगिक इलैक्ट्रानिक्स 4 संवर्धन कार्यक्रम 2.50 2852 2.50 2.50 2.50 ... 5. सेमी-कंडक्टर काम्पलेक्स लि. 2852 10.00 10.00 0.10 0.10 इलेक्ट्रोनिकी संघटक 6. और सामग्री विकास कार्यक्रम 2852 5.50 0.60 5.50 0.60 6.10 10.00 0.60 10.60 6.10 सूक्ष्म इलेक्ट्रोनिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम-एन.एम.सी. 2852 4.00 4.00 4.00 4.00 40.00 40.00 उन्नत परिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) 2852 40.00 3.00 43.00 40.00 3.00 43.00 60.00 3.00 63.00 अनप्रयक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रोनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर) 2852 18.00 3.00 21.00 18.00 3.00 21.00 20.00 3.00 23.00 10. मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम 2852 23.00 4.30 27.30 23.00 4.30 27.30 24.00 4.30 28.30 4859 7.50 7.50 7.50 7.50 14.00 14.00 जोड़ 30.50 4.30 34.80 30.50 4.30 34.80 38.00 4.30 42.30 11. एएसआईसी डिजाइन हेत् विशेष जनशक्ति 2852 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 ... साफटवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास 7.00 2852 7.00 7.00 7.00 20.00 20.00 ... फोटोनिक/ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिकी 2852 3.00 3.00 3.00 3.00 ... परिवहन और विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी 2852 3.50 3.50 3.50 3.50 महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का विकास 2852 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 शैक्षणिक अनसंधान नेटवर्क (ईआरएनईटी) 2852 0.20 0.20 0.20 0.20 ग्रामीण/सामाजिक/कृषि/जल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स 2852 0.20 0.20 0.20 0.20 स्वास्थ्य और जैव सूचना में इलेक्ट्रॉनिकी 2852 6.00 6.00 6.00 6.00 14.00 14.00 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित रोजगार सृजन 2852 1.00 1.00 1.00 1.00 ईएससी और निर्यात बाजार विकास कार्यक्रम 2852 8.50 8.50 8.50 8.50 ... 21. अन्य कार्यक्रम 21.01 इलेक्ट्रोनिकी में प्रदर्शनी 2250 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 21.02 विदेशी व्यापार 3453 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 21.03 आई.पी.आर. संवर्धन कार्यक्रम 2852 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 21.04 अन्य स्कीमें 2852 1.60 0.50 2.10 0.50 0.50 0.50 1.60 2.10 जोड़ 2.60 4.40 7.00 2.60 4.40 7.00 1.00 4.40 5.40 22. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल 3606 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50 2.50 *घटाइए -* कार्यकारी मुख्य शीर्ष को अन्तरण 3606 -0.50-0.50-0.50-0.50-2.50-2.50... निवल - सहायता सामग्री और उपस्कर जोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित कें लिए परियोजनाओं/योजनाओं 2552 67.40 67.40 67.40 67.40 78.00 78.00 के लिए एकमुश्त प्रावधान 4552 7.60 7.60 7.60 7.60 15.00 15.00 जोड़ 75.00 75.00 75.00 75.00 93.00 93.00 24. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसीए) 2852 5.00 5.00 5.00 5.00 30.00 30.00 इलेक्ट्रोनिक गवर्नेस 2852 193.00 193.00 175.20 175.20 266.00 266.00

सं.16/सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Website: http://indiabudget.nic.in

										(2	हरोड़ रुपए)
			बजट 2004-2005			संशोधित 2004-2005			बजट 2005-2006		
		मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	न जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भि	न्न जोड़
26	— भारतीय भाषा हेत्										
_0.	प्रौद्योगिकी विकास	2852	7.00		7.00	7.00		7.00	7.00		7.00
27.	ई-कामर्स एवं सूचना-सुरक्षा			•••						•••	
	(स्मार्ट कार्डों सहित)	2852	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00		8.00
28.	सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक/प्रमाणन और										
	नेटवर्क सुरक्षा	2852	4.00		4.00	2.80		2.80	7.00		7.00
29.	साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स										
	इंडिया एंड ई एच टी पी	2852	6.00		6.00				2.00		2.00
30.	मीडिया लैब एशिया	2852	65.00		65.00				1.00		1.00
31.	जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी										
	(सिटीजन पोर्टल्स सहित)	2852	7.00		7.00	7.00		7.00	6.00		6.00
32.	6										
	परियोजनाओं का संवर्धन, अनुसंधान										
	और विकास	2852	6.00		6.00	6.00		6.00			
33.	विद्या वाहिनी एवं ज्ञान										
	वाहिनी कार्यक्रम	2852	1.00		1.00	1.00		1.00	1.50		1.50
34.	डीओईएसीसी	2852	5.00	1.70	6.70	5.00	1.70	6.70	6.00	1.70	7.70
35.	डिजीटल डी एन ए पार्क	2852	5.00		5.00	5.00		5.00	10.00		10.00
36.	मैगाफैव की स्थापना	2852							10.00		10.00
कुल	-जोड़		750.00	36.00	786.00	650.00	35.00	685.00	929.30	36.00	965.30
ख.	सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास	बजट	आं.ब.	जोड	बजट	आं.ब.	जोड	बजट	आं.ब.	जोड
		शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.	
1.	सेमिकन्डक्टर काम्पलेक्स लि.	12859		0.05	0.05		0.05	0.05			
		जोड़		0.05	0.05		0.05	0.05			
अन्य	संस्थाएं/निकाय										
एन.र	पी.एस.टी/समीर/एसईपीपी/सी-डैक आदि	12859		139.22	139.22		139.22	139.22		158.26	158.26
जोड़				139.27	139.27		139.27	139.27		158.26	158.26
ग. ३	आयोजना परिव्यय :-										
1. ਫ੍ਰ	रसंचार और इलेक्ट्रोनिकी उद्योग	12859	506.90	139.27	646.17	406.90	139.27	546.17	654.60	158.26	812.86
2. ₹	चिवालय-आर्थिक सेवाएं	13451	168.10		168.10	168.10		168.10	181.70		181.70
3. Ч	र्वोत्तर क्षेत्र	22552	75.00		75.00	75.00		75.00	93.00		93.00
जोड़			750.00	139.27	889.27	650.00	139.27	789.27	929.30	158.26	1087.56

- 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ: यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालयीय व्यय उपलब्ध कराता है ।
- 2. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) : राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्यों, संघ शासित प्रदेशों तथा देश के जिला प्रशासनों को नेटवर्क बैकबोन तथा ई-शासन सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक मुख्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संगठन है । यह एक नेटवर्क मूल संरचना सुविधा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, अनुप्रयोग सेवा प्रदाता तथा सूचना-सामग्री एएसपी है ।
- 3. प्रोद्योगिकी विकास परिषद् परियोजनाएँ (पीडीसी) : इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर संचार, नियंत्रण एवं यंत्रीकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी, दूरसंचार तथा प्रसारण के क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन, विकास एवं इंजीनियरी को बढ़ावा देना तथा समर्थन प्रदान करना है ।
- 5. सेमीकण्डक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल) : एससीएल का उद्देश्य सामरिक संगठनों की विशेष रूप से उनकी मिशन उन्मुखी परियोजनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है । दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर, स्मार्ट कार्ड जैसे चुने गए प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादों के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का डिजाइन एवं विकास करना ।
- 6. इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास कार्यक्रम (ईएमडीपी): इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए एक सशक्त अनुसंधान एवं विकास/प्रौद्योगिकीय आधार का विकास करना तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की भावी आवश्यकताओं को पूरा करना और महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली इलेक्ट्रॉनिकी सामग्रियों के लिए समुचित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा उद्योग में लक्ष्य उन्मुखी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है।
 - 7. माइक्रो इलेक्ट्रॉनिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (एमईडीपी)

- : इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा उद्योग में जनशक्ति सहित एक सशक्त आधार का निर्माण करना और साथ ही देशीय इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए अनुप्रयोग विशिष्ट एकीकृत परिपथों (एसिक) को बढ़ावा देना तथा इसके उपयोग का प्रसार करना है।
- 8. उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) : यह अभिकलन एवं संचार तथा इससे उत्पन्न होने वाले अनुप्रयोगों के क्षेत्र में विभाग की एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था है ।
- 9. प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर): यह एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जो माइक्रोवेव, मिली-मीटरबेव तथा इलेक्ट्रा-मैग्नेटिक्स के उच्च प्रौद्योंगिकीय क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और इन प्रोद्योगिकियों के लिए अनुप्रयोगों के विकास का इसका एक निर्दिष्ट लक्ष्य है।
- 10. मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम (एसटीक्यूसी) : यह उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों तथा उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए परीक्षण एवं अशांकन सेवाएँ प्रदान करता है।
- 11. वीएलएसआई डिजाइन के लिए विशिष्ट जनशक्ति : इसका उद्देश्य वीएलएसआई डिजाइन तथा संबद्ध सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में बी.ई/बी.टेक/एम.ई,एमटेक तथा पीएचडी स्तर पर विशिष्ट जनशक्ति का प्रशिक्षण देना है, जिसमें शोध केन्द्रों तथा प्रतिभागी संस्थानों को शामिल किया जाता है।
- 12. सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास : इस कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धिमान सॉफ्टेयर निर्यात उद्योग की सहायता करने के लिए आवश्यक विशिष्ट जनशक्ति का निर्माण करना तथा उसे सुदृढ़ बनाना है, जिससे लक्षित निर्यात हासिल किया जा सके ।

- 15. सामिरक इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर विकास: इसका उद्देश्य रेडार, नौवहन सहायक उपकरणों, सोनार, अन्तर्जलीय इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों, लेसर तथा इन्फ रिड आधारित प्रणालियों, सुरक्षा प्रणालियों, आपदा प्रबंध प्रणालियों, भावी विमान संचालन प्रणालियों तथा अन्य सामिरक इलेक्ट्रॉनिकी प्रणालियों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित कार्यकलापों को सहायता प्रदान करना है।
- 18. स्वास्थ्य के लिए इलेक्ट्रॉनिकी: विभाग चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों तथा पुनर्वास उपकरणों के क्षेत्र में देश में उनके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है । देशीय चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने देश के कई अस्पतालों में ऐसे चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का नियोजन आरम्भ किया है, जिससे देशीय चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के बारे में चिकित्सा समुदाय में विश्वास पैदा हो सके ।
- 21. अन्य कार्यक्रम : इस प्रावधान में इलेक्ट्रॉनिकी में प्रदर्शनी, बौद्धिक सम्पदा अधिकार संवर्धन कार्यक्रम, विद्या वाहिणी ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम, विदेश व्यापार तथा अन्य योजनाएँ पर होने वाला व्यय शामिल हैं।
- 22. सहायता सामग्री एवं उपस्कर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री, उपस्कर तथा अन्य वस्तुओं के रूप में बाह्य सहायता को दर्शाया गया है ।
- 23. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान: सरकार के निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय योजनागत आबंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ योजनाओं के लिए निश्चित किया जाना है।
- 24. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) : सीआईसी अपने सीआईसी पोर्टल (www.cic.nic.in) के माध्यम से ई-मेल, इंटरनेट अभिगम, नागरिक केन्द्रित सेवाएँ तथा कृषि बाजार सूचना, अस्पताल आरक्षण तथा बोर्ड परीक्षा परिणाम जैसी वेव आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं ।
- 25. इलेक्ट्रॉनिक शासन: इसके जिए सरकार के आन्तरिक कार्यकलापों को सरल बनाने तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए नागरिकों एवं व्यवसायों के साथ अपने सम्पर्कों में सुधार करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का नियोजन किया जाता है । इसका लक्ष्य वर्तमान प्रयासों से आगे बढ़कर, महत्वपूर्ण कार्य नीतियों का पता लगाकर, सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करके, लागत में कमी लाकर और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पुनः परिभाषित करके सरकार के नये स्वरूप का निर्माण करना है । इसके उद्देश्य में कम लागत पर पूरे देश में सम्पर्क एवं अभिगम उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत न्यूनतम मूलसंरचना का प्रावधान सुनिश्चित करना भी शामिल है ।
- 26. भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल): इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी साधनों तथा सूचना-सामग्री का विकास करना है, जिससे भारत में कम्प्यूटरों तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का प्रयोग अपनी भाषाओं में करने की सुविधा प्राप्त हो ।
- 27. ई-वाणिज्य एवं सूचना सुरक्षा : ई-वाणिज्य का उद्देश्य देश में ई-वाणिज्य के लिए एक सम्पूर्ण विधायी एवं विनियामक ढाँचा उपलब्ध कराना और व्यवसाय तथा वाणिज्य में सूचना सुरक्षा एवं ई-वाणिज्य की विभिन्न विशेषताओं तथा इनके लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है ।
- 28. सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक/प्रमाणन एवं नेटवर्क सुरक्षा : देश में अंकीय हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए तीन प्रमाणन प्राधिकारियों को लाइसेंस प्रदान किया गया है । इनमें राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) तथा टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज् (टीसीएस) शामिल हैं ।
- 29. भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई): एसटीपीआई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है । इसकी स्थापना अपने संवर्धनात्मक कार्यकलापों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं के क्षेत्र में भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए की गई है । इसे

- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न निर्यात उन्मुखी योजनाओं के संचालन, कार्यान्वयन तथा निगरानी की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।
- 30. मीडिया लैब एशिया: मीडिया लैब एशिया अद्यतन तकनीकी जानकारी की प्रौद्योगिकियों के लाभ जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए इस उद्देश्य से कार्य कर रही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है । यह शिक्षण, स्वास्थ्य तथा उपक्रम की बृहत् चुनौतियों को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी 10-वर्षीय योजना है ।
- 31. जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (दूर-औषधि): कम्प्यूटरों की इंटर-नेटवर्किंग तथा संचार प्रौद्योगिकियों के विकास से कम लागत वाली दूर- औषधि प्रणालियों के नियोजन की संभावनाएँ पैदा हुई हैं। दूर-औषधि मुख्यतः रोगों के निदान एवं उपचार के लिए दूरसंचार के प्रयोग से संबंधित है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक तात्कालिक माध्यम है।
- 33. विद्या वाहिनी और ज्ञान वाहिनी कार्यक्रम : यह कार्यक्रम प्रभावी शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली की स्थापना को सुनिश्चित करने और कक्षाओं में प्रौद्योगिकी लाने के लिए उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं का संयोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम रखने के लिए वर्ष 2002-2003 में शुरु किया गया है । सरकारी विरष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संयोजन के लिए और उच्चतर प्रशिक्षण संस्थाओं में सूचना प्रौद्योगिकी आधार ढांचे के उन्नयन के लिए क्रमशः दो विशेष कार्यक्रम अर्थात "विद्या वाहिनी" और "ज्ञान वाहिनी" नेटवर्क शुरु किए जा रहे हैं । इसका लक्ष्य दसवीं योजना के दौरान प्रत्येक स्कूल और शिक्षण संस्था में एकीकृत वॉयस, डाटा और वीडियो नेटवर्क स्थापित करना है तािक प्रत्येक विद्यार्थी अपेक्षित सूचना का प्रबंधन करने और संप्रेषण करने के लिए बहुपक्षीय बुनियादी कौशल और सक्षमता प्राप्त कर सके ।
- 34. डीओईएसीसी: डीओईएसीसी देश में कम्प्यूटर शिक्षण सहित तकनीकी शिक्षण के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) का एक संयुक्त प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र में संस्थानों/संगठनों के पास उपलब्ध सुविधाओं एवं मूलसंरचना का उपयोग करके सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है।
- 35. डिजिटल डीएनए पार्क : जैव प्रौद्योगिकी-डीएनए पार्कों का उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास के लिए सही मूलसंरचनात्मक सुविधाएँ एवं स्थान उपलब्ध कराना तथा भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में वृद्धि करना है । जैव प्रौद्योगिकी अथवा डीएनए पार्कों का विकास उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में सुधार करने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया जाएगा।
- 36. मेगा फैब की स्थापना: माइक्रोइलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रमुख समर्थनकारी प्रौद्योगिकी है। बहुत बड़े पैमान के एकीकृत परिपथ (आईसी) इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर तैयार करने के आधारभूत अंग हैं। इन आईसी का उत्पादन वेफर संरचना सुविधाओं में किया जाता है, जो मेगा फैब के नाम से भी परिचित हैं। हार्डवेयर उद्योग के विकास में आईसी का महत्त्व बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी इसका महत्व बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकीय परिष्करण, मूल्यों में कमी, कार्यनिष्पादन में सुधार तथा उत्पादों की उच्चतर गुणवत्ता के माध्यम से हासिल होता है। विकसित तथा विकासशील देशों की सरकारों ने समुचित प्रोत्साहन पैकेजों के जरिए मेगा फैब की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें व्यापार एवं शुल्क नीति, उपदान, कर रियायत अवधि, वित्तीय सहायता आदि शामिल हैं। इस प्रकार, मेगा फैब की स्थापना का प्रावधान देश में ऐसी सुविधाएँ स्थापित करने के लिए सरकार की वित्तीय प्रतिभागिता के लिए एक समर्थनकारी तंत्र के रूप में है।